संस्थापक : पं० कृष्णवल्लभ पाण्डेय

डाक पंजीकरण संख्या - एल/डाक पंजीकरण/रणनाद/के.पी.(एम.)/24-26 ''रणनाद'' दिनांक 12.12.2023

E-MAIL :- RANNAD@rediffmail.com
shak 313@indiatimes.com

साप्ताहिक

रणनाद

सम्पादक : आशा वाजपेयी एम.ए.बी.एड., अंजुली पाण्डेय एम.ए., एल.टी., अरुण पाण्डेय एम.एस.सी., एम.एड.,
शक्ति वाजपेयी : मयंक वाजपेयी : अनुपम वाजपेयी : आकाश पाण्डेय : वरुण पाण्डेय
कार्यालय-मसवासी, उन्नाव ☎0515-2833079 मो0-9628814978, 9936767386,
9336313412, 9044947970, 8765081098, 9044525219, 8563962112

वर्ष 60 : अंक 15 : 30 अप्रैल, 2024 मसवासी, उन्नाव : मंगलवार : पृष्ठ 4 : मूल्य 1 रुपया

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार

''बैंड बाजे के साथ विदाई करेंगे''

बोले- ये 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे

लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर बड़ा वार करते हुए इसे 'दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार' करार दिया। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण खत्म करने का मंसूबा रखने वाला यह परिवार अब चुनाव में वोट के लिये आरक्षण नहीं समाप्त करने की बात कर रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था, अब वोट चाहिए तो कह रहे आरक्षण खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं अगर सरकार की बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या उनमें आरक्षण होगा? सपा नेता ने कहा कि इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा वालों की बैंड बाजे से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यही संविधान है जो हमें हक, अधिकार दिलाता है। संविधान ही हमारी संजीवनी है। संविधान बचाने के लिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना। अपना वार करते हुए उन्होंने कहा कि आज रेजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया गया है, चीन ने आपकी जमीन कब्जा कर ली है, चीन आपके शहरों के, गांवो के नाम बदल रहा है और जनता को आप क्या दिखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं च्च। के लोगों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि पीडीए परिवार जीतेगा, और च्च। ही संविधान बचाएगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। यादव ने एटा में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक 'बड़ी साजिश' के तहत हर क्षेत्र को निजी हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है मगर समाजवादी लोग उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने संघ परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए किसी का नाम लिये बगैर कहा, ''इन्हें (भाजपा को) हमारे–आपके परिवार की तो चिंता है लेकिन उनके साथ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए, तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा।'' माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष का इशारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के रविवार के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ ने हमेशा संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन किया है और संगठन 'भेदभाव व्याप्त रहने तक आरक्षण लागू रखने की वकालत करता है। यादव ने कहा, ''मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार की बड़ी–बड़ी कंपनियां निजी हाथों में बिक जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? इस सरकार ने हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेच दिये, जिनमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी... बताओ क्या वहां आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो 'आउटसोर्स' पर नौकरी दी जा रही है, क्या उसमें आरक्षण होगा? संविदा पर दी जाने वाली नौकरी में क्या आरक्षण होगा?''

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान ईवीएम से डाले गए मतों से करने संबंधी याचिका खारिज की

नयी दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपैट) पर्चियों का मिलान 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (ईवीएम) के जरिये डाले गए मतों से करने का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि शीर्ष अदालत की एक पीठ ने इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते अपना फैसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि एक पीठ पहले ही निर्णय सुना चुकी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जब कहा कि मुद्दा पारदर्शिता का है और शीर्ष अदालत ने कुछ उपाय सुझाये थे, इस पर न्यायालय ने कहा, ''एक अन्य पीठ दो दिन पहले एक आदेश जारी कर चुकी है।'' न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 26 अप्रैल को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें ईवीएम से डाले गए मतों का वीवीपैट पर्चियों के साथ पुनरू सत्यापन करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थानों पर रहने वाले (असफल) उम्मीदवारों को एक विकल्प प्रदान करते हुए उन्हें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिशत ईवीएम में लगी 'माइक्रोकंट्रोलर' चिप के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि इसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग को शुल्क अदा करना होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक मई से, चिह्न 'लोड' करने वाली यूनिट को सील किया जाए और एक कंटेनर में भंडारित किया जाए तथा चुनाव परिणाम की घोषणा से कम से कम 45 दिन की अवधि के लिए 'स्ट्रॉग रूम' में इन्हें ईवीएम के साथ रखा जाए।

अमित शाह के फेक वीडियो मामले में पीएम मोदी ने ईसी से कर दी बड़ी अपील

कहा- समाज में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही

नयी दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सतारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी ने कहा कि फर्जी वीडियो के जरिए समाज में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है। देश में लोकतंत्र, शांति और सद्भाव के लिए मैं देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि वे फर्जी वीडियो और तस्वीरों को उजागर करें और पुलिस को रिपोर्ट करें। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद करने का नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि समाज को फर्जी वीडियो से बचाना हमारी जिम्मेदारी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हजारों टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता था। कांग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तैयार नहीं थी। मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बांटे। भाजपा ने पहले आरोप लगाया था कि तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो प्रसारित किया गया था जिसमें उन्हें एससी–एसटी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण को हटाने का झूठा वादा करते हुए दिखाया गया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि छेड़छाड़ किया गया वीडियो कथित तौर पर आधिकारिक तेलंगाना कांग्रेस के एक्स हैंडल द्वारा साझा किया गया था और उसके बाद, पार्टी के कई नेताओं ने इसे दोबारा पोस्ट किया। इस बीच, दिल्ली पुलिस साइबर सेल की एक टीम अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल को नोटिस जारी करने के लिए सोमवार को तेलंगाना के लिए रवाना हुई, जिसमें उन्हें कथित तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण को खत्म करने का वादा

सम्पादकीय

मणिपुर का क्या होगा ?

मणिपुर में हिंसा भड़के एक साल पूरा होने जा रहा है। पिछले वर्ष मई के पहले सप्ताह में वहां हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब तक इस पर लगाम लगने को कोई संकेत नहीं है। बीते शनिवार को सीआरपीएफ के दो जवानों की हत्या कर दी गई। उसी मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में कुकी समुदाय की एक महिला की भी मौत हो गई। रविवार को फिर एक व्यक्ति की जान गई। इस वर्ष एक रुझान यह देखने को मिला है कि सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्य के लोगों– खासकर कुकी समुदाय में पुलिस और केंद्रीय बलों को लेकर भारी नाराजगी है। पिछले साल भी कई जगह महिलाओं ने केंद्रीय बल के जवानों को अपने इलाके में नहीं घुसने दिया था। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान कई इलाकों से ईवीएम में तोड़–फोड़, वोटरों को धमकाने और हिंसा की कई खबरें सामने आई थी। इन घटनाओं के कारण अनेक मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि पिछले एक साल में हत्या और आगजनी के छह हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और करीब दो सौ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य में 36 हजार सुरक्षाकर्मी और अतिरिक्त 40 आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। फिर भी हालात संभल नहीं रहे हैं। स्पष्टतः इसका कारण यह है कि मणिपुर में जारी हालात सिर्फ कानून–व्यवस्था की समस्या नहीं हैं। बल्कि ये सामाजिक स्तर पर चौड़ी होती गई खाई का परिणाम हैं। आरोप यह है कि सामुदायिक आधार पर अविश्वास की खाई को बढ़ाने में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भी भूमिका रही है। गौरतलब है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई तबके को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद राज्य में हिंसा भड़की थी। आरोप है कि बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए राज्य सरकार ने एकतरफा नजरिया अपनाया। केंद्र की भूमिका भी संदिग्ध रही है। नतीजा, मणिपुर का एक नासूर में तब्दील हो जाना है। यह नासूर गहराता ही जा रहा है।

व्यंग्य दास नहीं..... उदास वोटर

देश में उदास वोटर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना दास नहीं बना सकी न ही चुनाव करवाने वाले अपनी अदाओं से प्रभावित कर सके। ये इस बार के महाचुनाव के पहले चरण में वोट डालने नहीं गए। वोटिंग में आई गिरावट को उठाने के लिए प्रयास जारी हैं जो तकनीकी ज्यादा लगते हैं। अभियान चलाए जा रहे जिन्हें मिनी आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। प्रशासनिक प्रयास भी हमेशा सीमित और उदास होते हैं। जिन कम्पनियों ने करोड़ों का चंदा दिया, कोशिश कर रही हैं। उन्हें कहीं से खास संदेश आया होगा। अपने कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी, घर से काम की सुविधा दे रही हैं। वोटर को निर्वाचन क्षेत्र में भेजने की योजना है। सीमेंट वाले प्रत्येक प्रतिज्ञा के लिए एक किलो सीमेंट दान करने की बात कर रहे हैं। देशभक्ति प्रेरित विज्ञापनों के इलावा हालांकि प्रतिज्ञाएं दिलाई जा रही हैं लेकिन सब जानते हैं कि अधिकांश लोग सिर्फ मुंह से प्रतिज्ञा लेते हैं दिल और दिमाग से नहीं और जल्दी भूल भी जाते हैं। दरअसल हम परम्पराओं के शिकंजे में गिरफ्तार रहने वाले मतदाता हैं। हमें नकद और वस्तु के रसपान की पुरानी समृद्ध परम्परा अभी भूली नहीं। हमें विज्ञापन कम, सामान की फ्री डिलीवरी ज्यादा पसंद है। कुछ लेकर कुछ देना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका स्वाद थोडा बदल गया होगा तो ऐसे भी होंगे जो नए होंगे और कुछ नया स्वादिष्ट चाहते होंगे। शादी में हर कुछ उपहार की जगह, नकद लेना सभी पसंद करते हैं। वोट न देना भी एक किस्म की नाराज उदासी दिखाना है। यह अनमनापन है। व्यवस्था के खिलाफ शांत प्रदर्शन है। वोट न देने वाले उदास वोटरों को अपनी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं दिखता। उन्हें लगता है किए जा रहे उपाय कुछ दिनों के लिए हैं। यह बात हैरान करती है कि युवाओं में वोट डालने की ललक नहीं है। तम्बू के नीचे पीने का पानी पिलाना, गर्म हवा ही फेंक रहे पंखे क्या कर सकते हैं। जागरूकता फैलाने का क्या है जनता महा जागरूक है। साक्षरता भी क्या करेगी, यहां तो पढ़े लिखे अनपढ़, धर्म भीरु, अंधविश्वासी हैं। नुक्कड़ नाटक, खेल और साइकिल रैली तो मनोरंजन है। ध्यान रहे हमारे यहां तो जेल से बार बार पैरोल पर आने वाले बाबा के इशारे पर लाखों वोट डाले या नहीं डाले जा सकते हैं। मतदाताओं की उदासी कम करने के लिए स्थानीय और मौसमी फल, मौसम के हिसाब से टोपी, नेकर, टमाटर, आलू, पानी या तरल, दो चार दिन का पैक खाना भी उदासी को संतुष्टि में बदल सकते हैं। नवोन्मेषी विचारों की क्या कमी है दुनिया में। कुल मिलकर वोटिंग का दिन, जिम्मेदार पिकनिक दिवस की तरह हो सकता है। –संतोष उत्सुक

कांग्रेस के मुद्दों पर लड़ रही भाजपा!

पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव को देखने और समझने का नजरिया बदल गया है। कम मतदान की अपने अपने अंदाज में व्याख्या हो रही है। विपक्षी पार्टियां इसे सरकार के प्रति मोहभंग मान रही हैं तो भाजपा का कहना है कि विपक्ष से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इसलिए सिर्फ सरकार का समर्थन करने वाले ही बूथ पर जा रहे हैं। कहने की जरुरत नहीं है कि दोनों धारणाएं अतिवादी हैं। सचाई दोनों के बीच कहीं है। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार ही बदल गया है। भाजपा अब तक जिन मुद्दों पर प्रचार कर रही थी वो सारे मुद्दे हाशिए में चले गए हैं। उनकी जगह नए मुद्दे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नए मुद्दे आसमान से टपके हैं। ऐसा भी नहीं है कि अचानक कोई बड़ा घटनाक्रम हो गया और समूचा नैरेटिव बदल गया। ये नए मुद्दे आए हैं कांग्रेस के घोषणापत्र से या कांग्रेस नेताओं के बयानों से। सो, कह सकते हैं कि अब चुनाव कांग्रेस के घोषणापत्र पर या कांग्रेस के तय किए गए एजेंडे पर लड़ा जा रहा है। यह कई मायने में कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है कि उसके चुने गए मुद्दे पर चुनावी नैरेटिव सेट हो रहा है। ध्यान रहे पिछले 10 साल से राजनीति का समूचा विमर्श भाजपा और खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे थे। वे मुद्दे तय करते थे, उसे जनता के बीच ले जाते थे और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते थे। उनके साथ साथ देश की जनता भी कांग्रेस से सवाल पूछती थी। देश को कांग्रेस ने 60 साल के शासन में क्या दिया, यह आम जनता का सवाल हो गया था। राहुल गांधी को कैसे कमान दी जा सकती है, यह भी देश का सवाल बन गया था। भारत का विकसित होना और इसके गौरवशाली इतिहास की वापसी तभी मुमकिन है, जब मोदी हैं, यह भी देश का सबसे लोकप्रिय विमर्श था। लेकिन इस बार के चुनाव में यह विमर्श नहीं है और अगर है भी तो सार्वजनिक स्पेस में उसकी उपस्थित नगण्य है। इस बार के चुनाव में भाजपा की ओर से बरसों के परिश्रम से स्थापित किए गए मुद्दों की बजाय कांग्रेस की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हो रही है। संविधान बदलने का मुद्दा कांग्रेस जनता के बीच लेकर गई थी। आज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है। जान देकर संविधान बचाने की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी आ गए तो अब संविधान को नहीं खत्म कर सकेंगे। यह कहने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस ने आम लोगों के मन में संदेह का बीज बो दिया है। अनुसूचित जातियों को लग रहा है कि भाजपा बाबा साहेब के बनाए संविधान को समाप्त कर देगी। पिछड़ी जातियों को लग रहा है कि भाजपा संविधान बदल कर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेगी। मुसलमान और व्यापक रूप से देश की धर्मनिरपेक्ष जनता को लग रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को बदल कर भाजपा उसमें से 'सेकुलर' शब्द हटा देगी। दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों की पार्टियों और कुछ हद तक नागरिकों को भी लग रहा है कि भाजपा संघवादी शासन व्यवस्था को खत्म कर देगी। इसी तरह भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म करके एकरूपता लाने की चिंताओं पर भी देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चा हो रही है। सो, संविधान बदलने का जो खतरा कांग्रेस दिखा रही थी उसे खारिज करने की तमाम कोशिशें अभी तक निरर्थक होती दिख रही हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया खतरा दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में संपत्तियों के पुनर्वितरण की बात कही है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है और वह लोगों की संपत्ति छीन कर 'ज्यादा बच्चे वालों' और 'घुसपैठियों' को दे देगी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक रंग दिया और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के 2006 में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस मानती है कि देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक असमानता दूर करने के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण की जो बात कांग्रेस ने कही है उसे जाने अनजाने में प्रधानमंत्री मोदी ने विमर्श का मुद्दा बना दिया है। इसमें सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर का तड़का लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत में मिली संपत्ति के ऊपर कर लगता है और वह 55 फीसदी तक होता है। ध्यान रहे भारत में भी ऐसा कर लगता था, जिसे 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने खत्म किया था। अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सचमुच कांग्रेस सरकार में आएगी तो वह कुछ लोगों यानी अमीरों की संपत्ति लेकर आम लोगों यानी गरीबों में बांट देगी? ध्यान रहे भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं। करीब 81 करोड़ तो ऐसे हैं, जिनको सरकार पांच किलो मुफ्त अनाज दे रही है और बड़े गर्व से इसका प्रचार भी कर रही है। अगर ऐसी जनता को यह बात समझ में आती है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उसको कुछ संपत्ति या कुछ पैसे मिल सकते हैं फिर क्या होगा? संभव है कि छोटा सा मध्य वर्ग या अति सूक्ष्म आकार का भारतीय उच्च वर्ग इस बात से आहत हो रहा हो या परेशान हो सकता है लेकिन ज्यादा बड़ी आबादी को यह विचार ही रोमांचित करने वाला है कि सरकार अमीरों की संपत्ति लेकर उसे जनता में बांट सकती है। याद करें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर क्या इसी तरह का वादा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था? फर्क इतना है कि उन्होंने विदेशों में जमा कारोबारियों के धन को काला धन कहा था। उन्होंने बताया था कि यह काला धन इतना ज्यादा है कि भारत आ जाए तो हर भारतीय के खाते में 15–15 लाख रुपए आ सकते हैं। सोचें, यह बात लोगों को कितनी अच्छी लगी थी और कैसे सब लोग अच्छे दिन आने के सपने देखने लगे थे! अभी हाल के दिनों में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसका कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए पैसे उन लोगों में बांटे जाएं, जो लूट का शिकार हुए हैं। यह भी संयोग है कि इसी समय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) को लेकर बहस चल रही है। नौ जजों की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि निजी संपत्ति को सामुदायिक बेहतरी के लिए सरकार कब्जा कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जज करीब 60 साल पहले ऐसे ही एक मामले में जस्टिस बी कृष्णा अय्यर के फैसले से सहमत दिख रहे हैं। जस्टिस अय्यर ने कहा था कि 'भौतिक जगत में ऐसी कोई भी चीज, जिसका मूल्य है और जिसका इस्तेमाल हो सकता है वह भौतिक संसाधन है और चूंकि हर व्यक्ति समुदाय का सदस्य है इसलिए उसके संसाधन का इस्तेमाल समुदाय के लिए हो सकता है'। जस्टिस अय्यर ने जब यह फैसला सुनाया था तब वे अल्पमत में थे। लेकिन उनकी बात बहुमत के फैसले से ज्यादा स्वीकार की गई। सो, असमानता दूर करने के लिए आर्थिक सर्वे, संपत्ति के पुनर्वितरण और विरासत कर की बातें सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत क्रांतिकारी विचार है, जिसे एक तबका प्रतिगामी भी मान सकता है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र बचाने, जाति गणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने, संपत्ति के पुनर्वितरण और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए एक बड़े तबके के साथ हुए अन्याय का पता लगाने के क्रांतिकारी विचारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए भाजपा को बाध्य कर दिया है। पिछले 10 साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है और भाजपा उस पर प्रतिक्रिया दे रही है।

–अजीत द्विवेदी

बसपा के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर आकाश आनंद ने

उम्मीदवार अशोक पांडेय के समर्थन में की जनसभा

बोले- युवाओं की नौकरी छीनकर राशन दे रही भाजपा

उन्नाव। बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो धन्नासेठों के बजाए मिशनरी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करती है। समाजवादी पार्टी जहां परिवार के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाती है। वहीं सबसे अधिक 60 वर्ष तक केंद्र में काबिज रही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते कभी एससी, एसटी व ओबीसी आदि को जनसुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यता नहीं समझी। इसी तरह भाजपा साल में करीब 12 हजार रुपए का राशन देकर कम से कम ढाई लाख रुपए सालाना आय वाली नौकरी न देकर वोट कब्जियाना चाहती है, वास्तव में यही गुजरात माडल है। इसलिए किसी के बहकावे में आए, बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए बसपा प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा पहुंचाना है। बता दें शहर स्थित रामलीला मैदान (साकेत धाम) में बसपा के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर आकाश आनंद ने पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार पांडेय के समर्थन में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कैडर (बसपा के मूल कार्यकर्ताओं) को आगाह किया कि नीला गमछा डालकर मिशन से भटकाने वालों से सावधान रहकर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए।

युवा कार्यकर्ताओं से पार्टी के मतदाताओं को भ्रमित करने वाले बहुरुपियों की चप्पलों से जमकर पिटाई करने की सलाह भी दी। कहा महंगाई कम करने और कालाधन वापस लाने के वादे पर फेल रहने वालों को अब तीसरी बार वोट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पकौड़ा तलने को रोजगार बता चुके लोग आगे सत्ता में आकर हाथ में कटोरा थमाकर भीख मांगने को भी रोजगार घोषित कर देंगे। देश की आधी आबादी यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा दुनिया के सामने भारत का मान गिराया जा चुका है। चुनावी वादे के मुताबिक सरकार ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराया होता, तो यह नौबत नहीं आती। नोटबंदी के बाद भी कलाधन वापस नही आ सका, क्योंकि सबसे अधिक कालाधन वापस लाने का दावा करने वालों के पास ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार ने शिक्षा को बदहाल बनाया है। इसीलिए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं उपलब्ध कराए गए है। सरकारी स्कूलों के बच्चे सामान्य जोड़–घटना के साथ अंग्रेजी के शब्द नहीं बोल पाते हैं। युवाओं से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा सरकार पेपर लीक करा रही है, वैसे ही इस चुनाव में उनका वोट भी लीक करके दिखा दीजिए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी से पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांगने की सलाह भी दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सपा चलाने वालों का पूरा परिवार चुनाव क्यों लड़ता है? क्या यादवों सहित ओबीसी व अन्य वर्गों में इस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलते? इसी तरह कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 60 वर्षों तक केंद्र में सत्तारूढ़ रहते हुए आखिर कभी बाबा साहब के अनुयायियों की सुधि क्यों नहीं आई। उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते मायावती द्वारा बालिकाओं की बेहतरी के लिए चलाई गई योजनाएं भी गिनाईं।

केवल कमल ! भारत में भी आ सकता है वन पार्टी सिस्टम ?

जिनपिंग–पुतिन की तरह मोदी थे, हैं और रहेंगे कितना मुमकिन

शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने भाजपा द्वारा भारत को चीन की तरह एकदलीय राष्ट्र बनाने का दावा किया। यही बात उनके पिता और शिवसेना उद्धव (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी यवतमाल जिले के दिग्रास में एक रैली को संबोधित करते हुए दोहराई और कहा कि भाजपा की वन नेशन वन पार्टी की योजना को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा खत्म हो रहा है। ठाकरे ने कहा कि एक राष्ट्र, एक कानून को समझा जा सकता है। लेकिन हम भाजपा की एक राष्ट्र, एक पार्टी योजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इससे पहले अप्रैल के शुरुआती महीने में दावा किया कि भाजपा देश में रूस और चीन जैसा शासन दोहराना चाहती है। तमाम चर्चाओं के बीच आज आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है, भारत के परिपेक्ष्य में वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है और ये चीन के पार्टी सिस्टम से कितना भिन्न है।

भारत और चीन, गांधी और माओ

चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और यह भारत की भारतीय जनता पार्टी (ठश्रच) की आधी है।साल 1917 में सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की जीत के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे चीन में फैल गई। जिसके बाद चीन के विचारकों को यह लगने लगा की देश को एकीकृत करने के लिए मार्क्सवाद ही सबसे ताकतवर हथियार है। 1919 में चीन में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इसी दौरान वहां मजदूर वर्ग एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। माओ तुंग ने एक जुलाई 1921 को सीपीसी की स्थापना की थी। साल 1937 में चीन पर जब जापान ने आक्रमण कर दिया तब कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी सेना आपस मे मिल गई। लेकिन जापान के हारने के बाद इन दोनों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस दौरान राष्ट्रवादी सेना पर कम्युनिस्ट सेना भारी पड़ी और 1949 में पूरे चीन पर माओत्से तुंग का शासन हो गया। 1949 में बना चीन जिसकी पहचान एक देश से ज्यादा कुछ चेहरों से होती रही। माओत्से तुंग चीन के पहले राष्ट्रपति और दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक तानाशाह। 1 अक्टूबर 1949 को जब माओ ने चीन की आजादी की घोषणा की तो खुद को उस देश का सबसे बड़ा नेता भी घोषित कर दिया था। चीन में इतना सबकुछ हो रहा था तो उसके पड़ोस भारत में क्या चल रहा था। जब चीन में गृह युद्ध छिड़ा था उसी क्षण, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बंबई और कलकत्ता के अंग्रेजी बोलने वाले वकीलों के प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी जन पार्टी बन गई।1950 तक, भारत और चीन दोनों ने विदेशी शक्तियों को बाहर कर दिया था और जहां भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। वहीं चीन माओ की किसान सेना या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बढ़ते कैडरों की बदौलत एक क्रांतिकारी राज्य बन गया। आने वाले दशकों में भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र बन गया, जबकि इसके उलट चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम।

सिंगल पार्टी सिस्टम

इस सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसका शासन होता है। ये अधिनायकवादी सिद्धांत सबसे पहले राजतंत्रों और में पाया जाता था। बाद में तानाशाही हुई और अब यह व्यवस्था कुछ लोकतांत्रिक देशों में मौजूद है। हालाँकि, ऐसे शासनों में भी केवल दिखावा दिखाने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मतदाता की पसंद केवल एक उम्मीदवार तक सीमित है। चीन में कम्युनिस्ट शासन के तहत एकदलीय शासन है तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो का प्रमुख ही राष्ट्रपति बनता है। चीन में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता मतदान नहीं करती। उदाहरण के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेते हैं जिसमें पांच अलग–अलग बॉडी होती है और इसमें पॉवर हरारकी का सिस्टम फॉलो होता है। मतलब सबसे ताकतवर सबसे ऊपर और उसमें कम ताकतवर उससे नीचे। पार्टी में सबसे ताकतवर पद जनरल सेक्रेटरी का होता है। इस पद के लिए हर पांच साल में चुनाव होते हैं।

बाई पार्टी सिस्टम

इस सिस्टम में दो पॉलिटिकल पार्टियां होती है। पार्टियों को मतदाताओं का पर्याप्त समर्थन

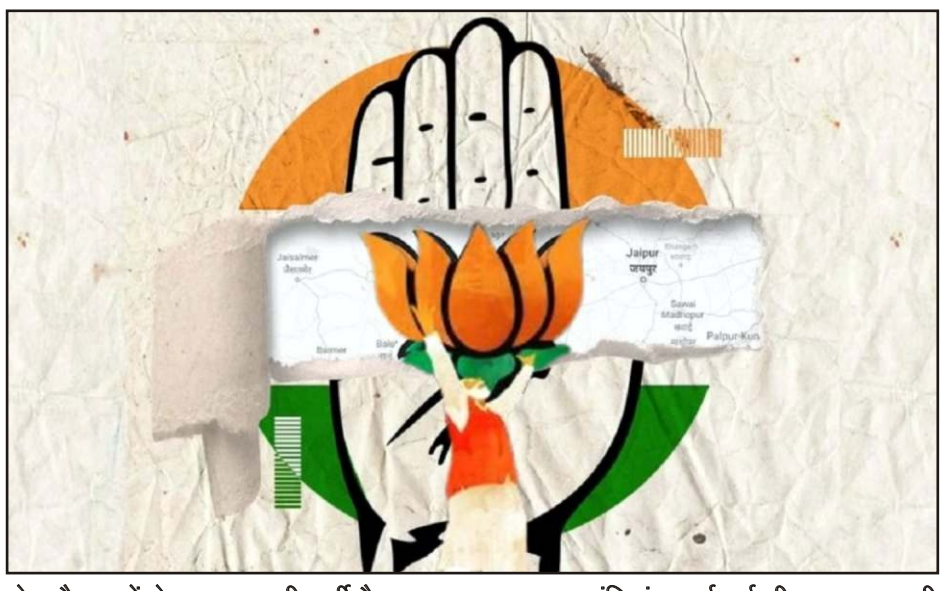

होता है। उनमें से एक सत्ताधारी पार्टी है, यह इस पर निर्भर करता है कि चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम बाई पार्टी सिस्टम के उदाहरण हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियाँ मुख्य पार्टियाँ हैं, और यूके में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दो मुख्य पार्टियाँ हैं।

मल्टी पार्टी सिस्टम

इस सिस्टम में कई पॉलिटिकल पार्टियां होती है। भारत और कई यूरोपीय देशों में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय में इस प्रणाली में कई पार्टियाँ मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं और अपनाती हैं।

भारत में एक ही पार्टी का होगा राज?

भारत में पहली ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी एक पार्टी को लगातार दो चुनाव में जीत मिली हो। न ही कोई ऐसा पहली दफा देखने को मिल रहा है कि किसी एक पार्टी का कई सारे राज्यों में शासन है। जवाहर लाल नेहरू के वक्त में कांग्रेस देश के अंदर सबसे मजबूत स्थिति में थी और उनके सामने विपक्ष महज औपचारिकता की भूमिका में था। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में एक दल के प्रभुत्व की व्यवस्था कोई नई नहीं है। नेहरू एरा को भी स्वर्णिम काल नहीं कहा जा सकता। वहां भी नागरिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। उस समय भी केरल की सरकार बर्खास्त की गई। उस वक्त बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी।

रूस और चीन से तुलना कितनी जायज

रजनी कोठारी ने जब कांग्रेस प्रणाली शब्द का इस्तेमाल किया तो उस प्रणाली के भीतर अलग अलग स्वर भी उसमें उभरकर सामने आई। लेकिन धीरे धीरे इस प्रणाली की खामियां भी सामने आईं। इसमें प्रभुत्वशाली जातियां तो आ जा रही थी लेकिन पिछड़ी जातियों को उतना स्थान नहीं मिल पा रहा था। फिर राममनोहर लोहिया ने उन्हें गोलबंद करके एक वैकल्पिक राजनीति तैयार की थी। चीन और रूस की तुलना भारत से करने से पहले वहां के शासन व्यवस्था को देखना होगा। चीन में एकल पार्टी व्यवस्था है और छोटी छोटी पार्टियां वहां अस्तित्व में तो हैं लेकिन सरकार बनाने की ताकत केवल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। वहीं रूस में पुतिन पिछले दो दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। विरोधी या विपक्ष की आवाज उठाने को लेकर अगर हम एलेक्सी नवलनी के उदाहरण पर गौर करें तो सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन भारत में इस तरह की बात करना कल्पना से परे लगता है।

–अभिनय आकाश

बसपा प्रत्याशी अशोक पांडेय ने भाजपा सांसद पर लगाया आरोप

जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत

उन्नाव। चुनाव हो और प्रत्याशियों का आरोप प्रत्यारोप न हो, ऐसा संभव नहीं। शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी अशोक पांडेय की तरफ से इसकी शुरुआत भी हुई है। आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज और विधायक ने कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान उन्हें डराया और धमकाया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम गौरांग राठी से इसकी शिकायत की है। जिसके बाद डीएम ने एडीएम न्यायिक को जांच के आदेश दिए हैं। बसपा प्रत्याशी अशोक पांडेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए गुरुवार को नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में भाजपा प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के अलावा छह विधायक और दो एमएलसी समेत दर्जनों लोगों के मौजूद रहने की बात कहते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि जहां पांच लोगों की मौजूदगी नहीं हो सकती है, वहां इतने लोगों की अधिकारी आवभगत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद ने विधायक अनिल सिंह की ओर इशारा करते हुए मुझे डराते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता (मुझे) बांधकर रखो, तभी जीत पाओगे। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि देख लूंगा, समय आने पर उनको मैं ढंग से झरिया दूंगा। विधायक अनिल सिंह ने धमकाने के लहजे में कहा कि सांसद ने अपने आश्रम में पांच–पांच भूत बांध रखे हैं, जो ब्राह्मणों के लिए काफी हैं। कहा कि मेरा नामांकन निरस्त करने का पूरा दबाव था। डीएम गौरांग राठी ने कहा कि बसपा प्रत्याशी की शिकायत पर एडीएम न्यायिक/प्रभारी एमसीसी को जांच अधिकारी नामित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच आख्या 27 अप्रैल 2024 को अपराह्न एक बजे तक उपलब्ध कराये। जांच में यदि दोष सिद्ध होता है तो संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

प्रेक्षक द्वारा पुरवा विधानसभा क्षेत्र 167 के मतदेय स्थलों का किया गया निरीक्षण

उन्नाव। लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा क्षेत्र 33–उन्नाव के लिए तैनात किये गये मा0 प्रेक्षक (सामान्य) श्री बाबू ए0 के द्वारा जनपद के विधानसभा क्षेत्र 167 पुरवा के मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय पाठकपुर विकास खंड असोहा में बूथ संख्या 218, 219 व 220 का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि वोटर गाइड लाइन वितरित की जाए, एएसडी सूची तैयार की जाए तथा बूथ के बाहर कुल मतदाताओं की सूची एवं हेल्प लाइन नम्बर का बोर्ड के साथ ही 200 मी0 की सीमा निर्धारित की जाए। इस अवसर पर मा0 प्रेक्षक ने ग्रामीणों से निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। इसके उपरान्त उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर विकास खंड असोहा के बूथ संख्या 373, 374 का निरीक्षण करते हुए बी0एल0ओ0 अरविन्द कुमार सिंह, सहायक अध्यापक को निर्वाचन सम्बन्धी कोई कार्य पूर्ण न होने के कारण निलम्बित करने के निर्देश दिये। उन्होने वोटर गाईड लाइन वितरित करने एवं एएसडी सूची तैयार करने के साथ ही एजेंट को निर्धारित स्थान पर मतदान के दिन बैठाने के भी निर्देश दिये। प्राथमिक विद्यालय मौरावां प्राचीन विकास खण्ड हिलौली में बूथ संख्या 313, 314 का निरीक्षण करते हुए वोटर गाईड लाइन वितरित करने, एएसडी सूची तैयार करने तथा एजेंट को निर्धारित स्थान पर मतदान के दिन बैठाने के निर्देश दिये। मा0 प्रेक्षक द्वारा विधानसभा क्षेत्र 167 पुरवा के निरीक्षण के दौरान पुरवा तहसील में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जोनल मजिस्ट्रेट के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु बैठक की गयी इसके उपरान्त निर्वाचन कन्ट्रोलरूम का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि एफएसटी टीम की जीपीएस के द्वारा लोकेशन ट्रेस करने के लिए कन्ट्रोलरूम में व्यवस्था की जाए। मा0 प्रेक्षक द्वारा जय किसान इन्टर कालेज चमियानी विकास खण्ड पुरवा में बूथ संख्या 113, 114, 115, 116 एवं 117 में निर्वाचन कराये जाने हेतु तैयारियों का निरीक्षण किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नाथी खेड़ा के बूथ संख्या 94 एवं 95 का भी निरीक्षण किया गया। पुरवा के चमियानी बाजार में प्लाइंग स्क्वॉयड टीम से क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की गयी। इस अवसर पर लाइजन ऑफिसर राकेश कुमार मिश्र उपस्थित रहे।

इन्डिया गठबंधन प्रत्याशी श्रीमती अन्नू टंडन ने मोहल्ला–मोहल्ला गली–गली में पैदल चल जनसंपर्क कर मतदान की अपील की

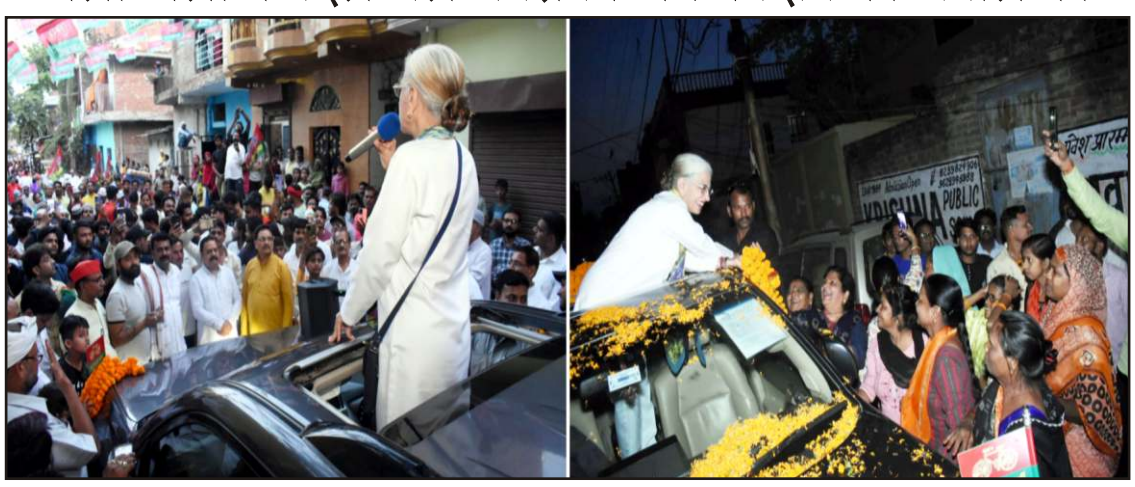

उन्नाव। नगरपालिका शुक्लागंज में इन्डिया गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती अन्नू टंडन ने मोहल्ला मोहल्ला गली गली में पैदल चल जनसंपर्क कर मतदान की अपील की जिनके पीछे पीछे चल रही अपार भीड़ अन्नू तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ के गगनभेदी नारे लगा लगातार उत्साह वर्धन कर रही थी। पूर्व सांसद श्रीमती अन्नू टंडन ने आज नगरपालिका शुक्लागंज के मोहल्ला शक्ति नगर ऋषि नगर बालूघाट मनोहर नगर अहमद नगर पोनी रोड़ चम्पा पुरवा आनन्दनगर झण्डे वाला चौराहा आदि मोहल्लों में भ्रमण कर मतदान की अपील की जिनके पीछे–पीछे चल रही भारी भीड़ अन्नू टंडन जिन्दाबाद अखिलेश यादव जिन्दाबाद के गगनभेदी नारे लगा लगातार उत्साह वर्धन कर रही थी, जहां आयोजित नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते श्रीमती अन्नू टंडन ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के लिए विख्यात उन्नाव की सरजमीं को भड़काऊ और नफरती भाषणों से विषाक्त बना दिया गया, तकिया पाटन में उन्नाववासी सदियों से मोहब्बत शाह की मजार पर चादरपोशी और सहस्त्र लिंगेश्वर मंदिर पर एक साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं लेकिन पिछले दस वर्षों में भड़काऊ भाषणों से जिस तरह से नफरत की फसल उगायी गयी है उससे उन्नाव की गंगा जमुनी तहजीब को छिन्न–भिन्न करने की भरसक कोशिश की गई लेकिन उन्नाव की बहुसंख्यक आबादी आपसी प्रेम और भाईचारे की पक्षधर हैं, लिहाजा आपसी प्रेम और भाईचारा आज भी कायम है। उन्होंने दस वर्षों से जिले का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद की कार्यशैली पर हमला बोलते हुए श्रीमती अन्नू टंडन ने कहा कि भाजपा ने उन्नाव को एक चुनावी सांसद दिया है जो केवल चुनाव में नजर आते हैं और जितने के बाद अपने आश्रम चलाते हैं उन्नाव के स्वास्थ्य शिक्षा यातायात तथा कानून व्यवस्था से उनका कोई लेना–देना नहीं है जिला अधिकारी कर्मचारी अफशर शाही की चाबुक से हांकते रहते और लोग समस्याओं और भ्रष्टाचार से पिसते रहते हैं उन्होंने आगामी 13 मई को ऐसे निष्क्रिय सांसद को हराने के लिए बढ़–चढ़कर मतदान की अपील की। शुक्लागंज भ्रमण के दौरान प्रमुख रूप से धर्मेन्द्र यादव, वीरेन्द्र शुक्ला, हाजी सैय्यद इरफान, शिवशंकर वर्मा, मन्टू कटियार, मंजीत यादव, उमालाल यादव, शुभ गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

भाजपा लोकसभा प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज ने गांवों में मांगा समर्थन

सफीपुर, उन्नाव। भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज ने रविवार को सफीपुर विकासखंड के दो दर्जन गांवों का दौरा कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपने लिए वोट मांगे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक बंबालाल दिवाकर ने डबल इंजन की सरकार द्वारा जनता को विकास की ओर ले जाने का संकल्प दोहराया। भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज ने मेथिकपुर में सचिन सिंह, अंबाहरा में ग्राम प्रधान लकी रावत, खरगौरा में अजय प्रताप सिंह, लहबरपुर में प्रधान प्रतिनिधि नन्हे सिंह व सलीम में ग्राम प्रधान दिनेश यादव के नेतृत्व मंर जनसंपर्क अभियान चलाया इसके बाद गौरी गांव में सभा में युवा, महिला, गरीब व किसान के मोदी जी कल्याण के संकल्प को दोहराया। कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सबका साथ सबका विकास एक साथ चल रहा है। इस दौरान विधायक बंबालाल दिवाकर ने सफीपुर के बहुमुखी विकास में साक्षी महाराज के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें हर समय सफीपुर की समस्याओं की चिंता रहती है। सभा का आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता अमित कुशवाहा व दीपक कुशवाहा ने किया। इस दौरान लारेंस विमल, गिरीश शुक्ला, जटाशंकर, देवीशंकर, पूर्व प्रधान भगवानदीन रावत, आशीष कनौजिया आदि शमिल थे। इसके बाद मवईभान, अटवा मोहाल ओसियां, बारीथाना आदि गांवों में सभा कर भाजपा को वोट देने की अपील की। उनके साथ अमितेश सिंह नंदू, भगवती प्रसाद रावत रहे।

पोस्टल बैलेट से पांच से सात मई तक होगा मतदान

उन्नाव। उन्नाव में पांच से सात मई के बीच पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जायेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांगजन व कोविड–19 से संक्रमित मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग कराया जायेगा। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी (अनुपस्थित मतदाता) सहायक अभिलेख अधिकारी देवेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान कराने के लिये गठित पोलिंग पार्टियां पांच मई को रवाना होंगी। जो इसी दिन मतदाताओं के घर पहुंचकर उनसे मताधिकार का प्रयोग कराएंगे। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने का सिलसिला सात मई तक जारी रहेगा। इस दौरान पोलिंग पार्टियों को प्राप्त होने वाली वोटरलिस्ट में शामिल सभी मतदाताओं के यहां दस्तक देने पहुंचना होगा। पोलिंग पार्टियों से प्राप्त होने वाले इस्तेमाल किये गये बैलेट पेपर को प्रतिदिन निर्धारित समयावधि में सहायक रिटर्निंग आफीसर के माध्यम से कोषागार में डबल लाक में सुरक्षित रखवाना होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक आशा वाजपेयी द्वारा शान्ति प्रेस, मसवासी, उन्नाव, उ०प्र० से मुद्रित एवं प्रकाशित। आरएनआई नं० पंजीयन सं० आर०एन० ६८१०/६५